बहुजन चेतना का वाहक

सबॉल्टर्न

अंक : 1 वर्ष : 1 फरवरी 2016 आवृति : त्रैमासिक मूल्य : 25 रुपये

- मंडल इतिहास का विराट जनादेश
- बिहार : चुनाव और मीडिया
- मि. भागवत! आरक्षण तो अभी शुरू हुआ है!
- जंगल राज बनाम 'जंगल राज'
- बिहार : इतिहास की नई दृष्टि
- विद्रोही : हिंदी कविता का सबॉल्टर्न स्वर
- मधेशी आंदोलन
- पोलैंड की नई वाम पार्टी– एजेम एवं अन्य विश्लेषण

बहुजन चेतना का वाहक

सबॉल्टर्न

वर्ष : 1 अंक : 1 फरवरी 2016

संपादकीय

खंड–1 : बिहार : चुनाव–विश्लेषण

3 मंडल इतिहास का विराट जनादेश
– अशोक यादव

8 बिहार : चुनाव और मीडिया
– उर्मिलेश

15 सेक्युलर–कम्युनल ध्रुवों के बीच की राजनीति
– खालिद अनीस अंसारी

20 बिहार में दलित–अति पिछड़ों के द्वंद्व
– नरेंद्र कुमार

24 वामपंथ : खोई जमीन पाने की जद्दोजहद
– शशि सागर

27 आधी आबादी की पूरी राजनीतिक गोलबंदी
– मंजू शर्मा

खंड–2 : चुनावी मुद्दे: वैचारिक–राजनीतिक संदर्भ

30 मि. भागवत! आरक्षण तो अभी शुरू हुआ है
– मनीष रंजन

38 वैदिककाल में गाय अवध्य और पूज्य नहीं थी
– प्रो. डी.एन. झा

41 जंगल राज बनाम 'जंगल राज'
– भुनेश्वर प्रसाद

खंड–3 : इतिहास दृष्टि

45 बिहार पर एक संक्षिप्त नोट्स
– प्रसन्न कुमार चौधरी

खंड–4 : वैश्विक क्षितिज

53 नेपाल का मधेश आंदोलन

56 राजनीति सिर्फ हार–जीत नहीं : इवा एलिस्जा

खंड–5 : रिपोर्ट

62 यह अंतर्विरोध नवजागरण और राजनीति दोनों में है : उर्मिलेश
– अरुण नारायण

खंड–6 : स्मरण

69 विद्रोही : हिंदी कविता का सबॉल्टर्न स्वर
– जितेंद्र यादव

अंक : 1 वर्ष : 1 फरवरी 2016
आवृति : त्रैमासिक
मूल्य : 25 रुपये
वार्षिक : 100 रुपये
आजीवन : 20000 रुपये

कार्यालय संपर्क :
22 किदवईपुरी,
पटना 800001
मोबाइलः 09471002942,
8292253306,
ईमेल : bagdor2016@gmail.com

परामर्श

ईश्वरी प्रसाद
ओ.पी. जायसवाल
उर्मिलेश
प्रेमकुमार मणि
शांति यादव

कम्पोजिंग एवं ले–आउट
अखिलेश कुमार/रवि भूषण गुप्ता

बागडोर द्वारा 22 किदवईपुरी, पटना से प्रकाशित एवं वातायन पटना से मुद्रित। संपादन अवैतनिक

शोध

महेंद्र सुमन
दिलीप मंडल

संपादन

अरुण नारायण
संतोष यादव
मनीष रंजन

प्रबंधन

मृगांक शेखर
अजीत कुमार
मणिलाल

नये दौर के एजेंडा को

ज्ञान और धन के न्यायपूर्ण बंटबारे पर केंद्रित करें

बिहार चुनाव में तमाम कयासों को झुठलाते हुए सबॉल्टर्न समाज ने जबर्दस्त रिजिलिअंस का परिचय दिया और अपने जनादेश से यह पुनर्स्थापित कर दिया कि बिहार बुनियादी रूप से जाति चेतना से लैस एक गतिशील समाज है और अभी भी भारत में सामाजिक न्याय का एक अभेद्यय दुर्ग बना हुआ है। यह आमतौर से भाजपा और खासतौर से नरेंद्र मोदी की ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी एवं कॉरपोरेटपरस्त राजनीति का नकार है। इसने बिल्कुल सही समय पर भाजपा रूपी पागल–उन्मत हाथी के पैरों को जंजीरों में बांध दिया और देश–दुनिया में न्यायप्रिय शक्तियों के बीच नई आशाओं का संचार किया है।

बिहार का यह जनादेश मंडल इतिहास का सबसे विवेकपूर्ण जनादेश है। बिहार विधान सभा की संरचना इतिहास में सबसे ज्यादा यहां तक कि सन् 1995 से ज्यादा समानुपातिक हो गई है। यह इस अर्थ में शानदार जनादेश है कि अकेले लालू यादव को मिला जनादेश नहीं है और न ही नीतीश कुमार को, बल्कि दोनों को मिला साझा जनादेश है। इसमें जरूरी चेक एंड बैलेंस मौजूद है और सबसे सुंदर साथ ही चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि बाहर संवैधानिक विपक्ष में नही, इसी गठबंधन के अंदर पक्ष तथा विपक्ष दोनों समाहित है। इतिहास में ऐसा जनादेश विरले ही मिलता है।

मंडल आंदोलन के पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान बहुजनों ने जो सम्मान और सत्ता पाई है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें इनसे वंचित नहीं कर सकती– बिहार चुनाव ने इसे फिर साबित कर दिखाया है। अब वह समय आ गया है कि हम मंडल के इस दूसरे दौर के संपूर्ण एजेंडा को धन और ज्ञान के न्यायपूर्ण वितरण पर केंद्रित करें। अब भी धन और ज्ञान के लगभग तमाम सूचकों के अनुसार बहुजनों का बड़ा तबका हाशिये पर है।

महागठबंधन ने नीतीश के 7 निश्चयों समेत 19 सूत्री साझा कार्यक्रम पेश किया है जिसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं– न्याय के साथ विकास, सामाजिक सौहार्द्र एवं स्वाभिमान। हमारी समझ से इन शब्दों की अंतर्निहित भावना है– बहुजनों के साथ न्याय, बहुजनों के बीच सौहार्द्र और बहुजनों के स्वाभिमान की रक्षा। बिहारी स्वाभिमान का पहला अर्थ है बहुजनों का स्वाभिमान, आगे आप चाहे जो भी अर्थ जोड़ लें। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के सही परिप्रेक्ष्य से कोई भी विचलन सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर करेगा।

उपर्युक्त 19 सूत्री कार्यक्रम में शामिल शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि यह बहुजन ही हैं जो सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे अधिक निर्भर हैं और उनकी बहुसंख्या कृषि में नियोजित है। इन सेवाओं की गुणवत्ता एवं कृषि का कायाकल्प किये बगैर उनके उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। 19 सूत्री कार्यक्रम में जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व और निजी क्षेत्र में आरक्षण का भी उल्लेख है। बहुजन जनता इन दो ज्वलंत मुद्दों पर महागठबंधन सरकार से बड़ी पहल की उम्मीद करती है।

पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान हमने देखा है कि देश में और बिहार में भी सामाजिक न्याय को लक्षित संस्थाएं– अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा आयोग, वित्त निगम आदि नकारा सिद्ध हुई हैं। यह जरूरी है कि आम गवर्नेंस में सवर्ण जातिवादी तत्वों के एकाधिकार को तोड़ने के साथ–साथ इन्हें भी अधिकार संपन्न, डेडिकेटेड और सक्षम संगठनों के रूप में विकसित किया जाए। यहां उल्लेख करते चलें कि सुधा की तर्ज पर विभिन्न क्षेत्रों, खासकर जातीय पेशागत उद्यमिता पर आधारित सहकारिता आंदोलन गेम चेंजर हो सकते हैं।

और आखिरी मगर सबसे महत्वपूर्ण– बिहार में इतिहास के सबसे नृशंस नरसंहारों के दोषी अलग–अलग न्यायालयों द्वारा दोष मुक्त हो रहे हैं। यह बिहार के न्यायपसंद और सभ्य समाज की सबसे बड़ी चुनौती है और नई सरकार से अपेक्षित है वह कि इन हत्यारों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए प्रयासों में तेजी लाएगी।

सबॉल्टर्न का यह अंक पिछले कई सालों से चल रही सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों की एक कड़ी है। हमारी कोशिश है कि न्याय की सामग्रिक अवधारणा– सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा लैंगिक न्याय– के तहत सामाजिक न्याय को केंद्र बिन्दु बनाते हुए एक व्यापक वैचाारिक मुहिम चलायी जाए। आज जिस तरह से सामाजिक न्याय की अवधारणा पर हमले हो रहे हैं, इस तरह की मुहिम से ही हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और सबसे बढ़कर बहुजनों की व्यापक एकता को मजबूत कर सकते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि यह समाज के जागरूक लोगों को लक्षित उनका एक साझा मंच हो। यह प्रवेशांक अपनी प्रतिबद्धताओं का कितना निर्वहन कर पाया है, यह आप सुधी पाठकों पर छोड़ते हैं।

रोहित वेमुला का अचानक चले जाना हम सबों को स्तब्ध कर गया। उनकी यह असाधारण मौत इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे हौसलों को नई ऊर्जा देगी। सबॉल्टर्न परिवार उनकी स्मृति को नमन करता है।

महेंद्र सुमन

बिहार चुनाव, 2015

मंडल इतिहास का विराट जनादेश

अशोक यादव

भाजपा को लंबे समय तक अफसोस रहेगा कि वह 2015 में बिहार में एक लगभग जीती हुई बाजी हार गई। भाजपा को इस बात का भी मलाल रहेगा कि नवम्बर, 2005 में जो बात समझ कर वह सत्ता पर कब्जा कर सकी थी, उसे 2015 में कैसे भूल गई। बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 के जनादेश को डिकोड करने के लिए हमें विगत पच्चीस सालों में बिहार में हुए चुनावों खासकर विधान सभा चुनावों के परिणामों में एक खास पैटर्न को समझना होगा।

लेखक सामाजिक न्याय मामले के विशेषज्ञ हैं। बिहार में मंडल विषयक मुद्दे पर इनका विशेष काम है।

1990 के बाद से ही भाजपा लालू को शिकस्त देने के अभियान में जुट गई। जिन बातों के चलते लालू इतिहास में चर्चा पाएंगे वह उनके द्वारा 1990–1995 में सामाजिक चेतना में बढ़ोत्तरी के लिए किये गए कार्य थे। लिहाजा 1995 के विधान सभा चुनाव में लालू को जनता ने जबर्दस्त समर्थन दिया। 1995–2000 में पशुपालन घोटाला और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भारी विफलताओं के चलते सन् 2000 के विधान सभा चुनाव में लालू की सत्ता जाते–जाते बची थी। इस चुनाव के पूर्व नीतीश भाजपा के साथ आ गए थे। किंतु वे चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किये गए थे। बिहार की जनता के सामने विकल्प स्पष्ट नहीं होने के चलते भ्रम की स्थिति थी कि पिछड़ी जाति की लालू–राबड़ी सरकार खत्म होने पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके चलते बिहार की जनता लालू के खिलाफ स्पष्ट जनादेश नहीं दे सकी। सात दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश बिहार विधान सभा में विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सके। राबड़ी देवी पुनः मुख्यमंत्री बनीं। 2005 के फरवरी महीने में लालू–राबड़ी के खिलाफ तो बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया किंतु भाजपा–जदयू गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश नहीं दिया। चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार भाजपा–जदयू गठबंधन द्वारा घोषित नहीं किये जाने के चलते बिहार की पिछड़ी जनता ने लालू को सत्ता से हटा दिया किंतु किसी को सत्ता नहीं सौंपी। पिछली बार की तरह जनता फिर आशंकित थी कि सत्ता कहीं पिछड़ा विरोधियों के पास नहीं चली जाए। भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों ने समझा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। इस बार भाजपा ने कोई गलती नहीं की, एक पिछड़े को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने में अपनी हिचकिचाहट का त्याग किया और चुनाव पूर्व नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस बार (नवम्बर, 2005 में हुए विधान सभा चुनाव) बहुसंख्यक जनता को कोई दुविधा नहीं थी। जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग को स्पष्ट जनादेश दिया और भाजपा गठबंधन की सरकार बिहार में बन गई। 2010 में बिहार की बहुजन जनता ने नीतीश कुमार को अभूतपूर्व जनादेश दिया जिसके पीछे मुख्य कारक स्थानीय निकायों– ग्रामीण एवं